



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

प्रयागराज, बुधवार 03 फरवरी, 2021 ई०  
(माघ 14, 1942 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (नि०नि०) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

अधिसूचना संख्या यू०पी०ई०आर०सी०/सचिव/नियमावली/516

अधिसूचना

दिनांक 03 फरवरी, 2021 ई०

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय तथा क्रय की गयी ऊर्जा का अनुकूलन), विनियमावली, 2021

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उपधारा (2) के अनुच्छेद (जेड०आई०) एवं (जेड०पी०), धारा 66, धारा 86 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (बी), (एच) तथा (के) तथा धारा 61 के अधीन प्रदत्त अधिकारों तथा इस निमित्त योग्य बनाये जाने हेतु अन्य समस्त प्राविधानों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग निम्न विनियमावली बनाते हैं :

#### 1-लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ-

- (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्यूनतम दरों से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय तथा क्रय की गयी ऊर्जा का अनुकूलन), विनियमावली, 2021 कहलायेगी।
- (2) यह विनियमावली अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

#### 2-परिभाषाएं-

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 तथा इसके तदनन्तर संशोधनों से है।
- (2) "एसी-यूबीसी" का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज एंडलॉस के साझाकरण) विनियम, 2020 के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

- (3) **“एजेसी”** का वही अर्थ होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2007 तथा इसके तदनन्तर संशोधनों में परिभाषित है।
- (4) **“उपलब्धता”** का वही अर्थ होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2007 तथा इसके तदनन्तर संशोधनों में परिभाषित है।
- (5) **“लाभार्थी”** का वही अर्थ होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2007 तथा इसके तदनन्तर संशोधनों में परिभाषित है।
- (6) **“सी0ई0ए0/प्राधिकारण”** का तात्पर्य, जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से है।
- (7) **“केन्द्रीय उत्पादन गृह”** का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमावली, 2010 (आई0ई0जी0सी0) में परिभाषित है।
- (8) **“कोल्ड स्टार्ट”** का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमावली, 2010 तथा इसके आदेशों में दिया गया है।
- (9) **“आयोग”** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है।
- (10) **“मांग”** का तात्पर्य चालू ऊर्जा की मेगावाट में मांग से है।
- (11) **“घोषित क्षमता अथवा डी0सी0”** का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमावली, 2010 तथा इसके आदेशों में दिया गया है।
- (12) **“वितरण अनुज्ञप्तिधारी”** का तात्पर्य जैसा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 (17) में परिभाषित से है।
- (13) **“एक्स-पॉवर प्लांट”** का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2007 में परिभाषित है।
- (14) **“हॉटस्टार्ट”** का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमावली, 2010 तथा इसके आदेशों में दिया गया है।
- (15) **“अन्तर्राज्य पारेषण पद्धति”** का वही अर्थ होगा जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित है।
- (16) **“अनुज्ञप्तिधारी”** का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित है।
- (17) **“बाजार”** का तात्पर्य ऐसे मंच से है जहां क्रेता और विक्रेता, या तो सीधे या ट्रेडिंग अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से, अथवा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से, विद्युत या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र अथवा ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र खरीदते या बेचते हैं।
- (18) **“अधिकतम सतत रेटिंग (एम0सी0आर0)”** का तात्पर्य वही होगा जो समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमावली, 2010 में परिभाषित है।
- (19) **“न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय (एम0ओ0डी0)”** का अर्थ है उत्पादन एवं पारेषण सुविधाओं की किन्हीं तकनीकी, विनियामक और परिचालकीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विचलनीय शुल्कों के आधार पर विद्युत गृहों द्वारा विद्युत की आपूर्ति न्यूनतम से बढ़ती हुई दरों के क्रम में दरों पर करना।
- (20) **“न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय हेतु ढाँचा (एम0ओ0डी0 स्टेक)”** का तात्पर्य अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियाँ तथा (एन-1) वें माह के तथा यदि (एन-1) वें माह के उपलब्ध न हो तब अन्तिम माह के ए0सी0-यू0बी0सी0 प्रभारों सहित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय तथा क्रय की गयी ऊर्जा का अनुकूलन) विनियमावली, 2020 की अनुरूपता में उत्पादन की आपूर्ति हेतु (एन-1) वें अथवा (एन-2) वें माह के लिए उपलब्ध विचलनीय प्रभारों के आधार पर तैयार किये गये ढाँचे से है।
- (21) **“विद्युत संयंत्रों का अनिवार्य रूप से चलना”** से तात्पर्य उन पवन, सौर ऊर्जा, बहती नदी पर जल विद्युत गृह (भंडारण के अतिरिक्त), परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत

संयंत्र अथवा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य विद्युत संयंत्र जिसकी दरें आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं अथवा अंगीकृत की गयी हैं :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की बैंकिंग अनिवार्य रूप से चालू मानी जायेगी तथा यह न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय आदेश से मुक्त होगी।

- (22) **“परिचालन”** का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड, 2007 तथा इसके तदनन्तर संशोधनों में परिभाषित है।
- (23) **“मेगावाट में ऑफ बार घोषित क्षमता”** का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमावली, 2010 तथा इसके आदेश में दिया गया है।
- (24) **“ऑनबार घोषित की गयी क्षमता”** का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युतग्रिड कोड) विनियमावली, 2010 और इसके आदेशों में दिया गया है।
- (25) **“स्पनिंग रिजर्व”** का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युतग्रिड कोड) विनियमावली, 2010 तथा इसके आदेशों में दिया गया है।
- (26) **“स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एस0एल0डी0सी0)”** का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित किया गया है और इसमें इसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे।
- (27) **“तकनीकी न्यूनतम”** का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमावली, 2010 तथा उसके तहत आदेशों में दिया गया है, बशर्ते कि आयोग द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।
- (28) **“विचलनीय प्रभार”** का तात्पर्य, जिन उत्पादन संयंत्रों की दरें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत सक्षम आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं, क्षमता प्रभार के अतिरिक्त लागू उत्पादन टैरिफ विनियमावली के अनुसार निर्धारित प्रभार होगा तथा जिन उत्पादन संयंत्रों की दरें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन सक्षम आयोग द्वारा अंगीकृत की जाती हैं प्रभार का अर्थ क्षमता प्रभारों के अतिरिक्त विद्युत क्रय अनुबन्ध में परिभाषित प्रभारों से होगा।
- (29) **“वार्म स्टार्ट”** का वही अर्थ होगा जैसा समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड), विनियमावली, 2010 तथा इसके आदेशों में दिया गया हो।
- (30) उपर्युक्त को सुरक्षित रखते हुए तथा सिवाय विषय के विपरीत होने अथवा विषय वस्तु की वांछना अन्यथा होने पर इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्द एवम् भाव जो यहां परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय ग्रिड कोड) नियमावली अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा आयोग को किसी अन्य विनियमावली में परिभाषित हैं तो उनका वही अर्थ होगा जैसा कि सम्बन्धित अधिनियम अथवा भारतीय विद्युत ग्रिड कोड अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की विनियमावली अथवा आयोग की अन्य विनियमावलियों में दिया गया है। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड तथा राज्य ग्रिड कोड के प्राविधानों में किसी भी विषमता के प्रकरण में उस सीमा तक जैसा आयोग के अभिमत में इन्हें लागू किया जा सकता है, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

### 3—लागू होने की सीमा—

यह विनियमावली राज्य भार डिस्पैच केन्द्र (एस0एल0डी0सी0), समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों सहित, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं, उत्पादन कम्पनियों पर लागू होगी :

परन्तु यह कि आर0पी0ओ0 और एच0पी0ओ0 के लक्ष्यों को पूरा करने तक अथवा जैसा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाये, चलते रहने चाहिए ऊर्जा संयंत्रों को इस विनियमावली से आच्छादित नहीं किया जायेगा।

#### 4—न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय (एम0ओ0डी0) की प्रक्रिया की तैयारी हेतु सामान्य शर्तें एवं सिद्धान्त

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन कम्पनी द्वारा लागू विनियमावली अथवा उत्पादन टैरिफ आदेश या सम्यक् आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत लागू आदेशों की अनुरूपता में उपलब्ध करायी गयी विचलनीय लागत के विवरणों को सत्यापित करेगा।
- (2) जहाँ भी लागू हो जैसा कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्य पारेषण प्रभार तथा हानियों के साझाकरण) विनियमावली, 2020 में विनिर्दिष्ट अन्तर्राज्य पारेषण हानियों तथा ए0सी0-यू0बी0सी0 प्रभारों सहित उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक उत्पादन गृह की विचलनीय लागत को संज्ञान में लेकर अनुज्ञप्तिधारी राज्य प्रणाली पर अन्तः राज्य तथा अन्तर राज्य उत्पादन स्रोतों के लिए न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया तैयार करेगा :

परन्तु यह कि प्रत्येक उत्पादन गृह से सम्बन्धित लागू अवधि की अन्तर्राज्य तथा पारेषण हानि एवं प्रभार (एन-1) वे माह के औसत पर आधारित होंगे तथा ऐसे प्रकरण में जहाँ गत माह की अन्तर्राज्य पारेषण हानि अथवा प्रभार उपलब्ध नहीं हैं तब उपलब्ध हानि अथवा प्रभारों को विचारित किया जायेगा।

- (3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी राज्य भार डिस्पैच केन्द्र (एसएलडीसी) को न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया उसी रीति में प्रस्तुत करेगा जैसा कि इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट है।
- (4) राज्य भार डिस्पैच केन्द्र अपने नियंत्रण क्षेत्र में क्रेता एवं विक्रेता के निर्धारण में सामंजस्य हेतु उत्तरदायी होगा। राज्य भार डिस्पैच केन्द्र इस विनियमावली, समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड, 2007 अथवा जैसा आयोग द्वारा निर्दिष्ट हो अन्य किसी विनियमावली में दर्शाये गये सिद्धान्तों को विचारित करते हुए न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया को लागू कराये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।
- (5) राज्य भार डिस्पैच केन्द्र निम्न को विचारित करते हुए न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय को संशोधित कर सकता है—

अ— जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचित किया गया उत्पादन इकाई द्वारा नयी व्यवस्था/अनुबन्ध के अधीन विद्युत की आपूर्ति का प्रारम्भ,

ब— इस आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत उत्पादन टैरिफ आदेशों के कारण न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में क्रय की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने हेतु विचलनीय प्रभारों का पुनरीक्षण।

स— ऊर्जा क्रय अनुबन्धों में विधि में परिवर्तन का प्रभाव जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के अनुमोदन के पश्चात अधिसूचित किया गया।

परन्तु यह कि उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत विचलनीय प्रभारों में पुनरीक्षण सम्यक् आयोग के आदेश की तिथि के 30 दिवसों के पश्चात् पड़ने वाले माह की पहली तिथि से प्रभावी होगा।

- (6) उन उत्पादन संयंत्रों के लिये जिनके ऊर्जा क्रय अनुबंध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन किये गये हैं न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय हेतु विचलनीय प्रभारों के लिये विधि में परिवर्तन के प्रभाव को भी सम्मिलित किया जायेगा, तथापि विधि में परिवर्तन के प्रभाव जिनसे विचलनीय प्रभार प्रभावित होते हों, जैसे करों में परिवर्तन, लेवी, शुल्क आदि के सम्यक् आयोग द्वारा उत्पादन कम्पनी विशेष के लिये अनुमोदित होने के तुरंत पश्चात्, उत्पादन कम्पनी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेगी।
- (7) एकल भाग टैरिफ वाले इन्ट्रा अन्तर्राज्य उत्पादन विद्युत गृहों के लिये न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय के लिये कुल टैरिफ को विचलनीय प्रभार विचारित किया जायेगा।
- (8) न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय के उद्देश्य से विचलनीय प्रभारों को दशमलव के 3 स्थान तक रु0—/ यूनिट में प्रस्तुत किया जायेगा।

**5—न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में क्रय की प्रक्रिया की तैयारी हेतु अवधि एवं तिथि—**

- (1) न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में क्रय के उद्देश्य से उत्पादन कम्पनी प्रत्येक माह की पहले एवं 15वें दिन तक ठीक पहले माह (एन-1) के विचलनीय प्रभारों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेगी।
- (2) (एन-1)वें माह के विचलनीय प्रभार के आधार पर न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया की तैयारी हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त उत्पादन संयंत्रों/इकाइयों से क्रय की गयी ऊर्जा के विचलनीय प्रभारों का विवरण सत्यापित करेगा तथा प्रस्तुत करेगा। जिस प्रकरण में तुरन्त पूर्व माह के विचलनीय प्रभार उपलब्ध नहीं हैं, उससे पूर्व (एन-2) वे माह के विचलनीय प्रभार संज्ञान में लिये जायेंगे तथा न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया की तैयारी हेतु प्रत्येक माह के 7वें तथा 22वें दिन को जिस विक्रेता के साथ ऊर्जा क्रय अनुबंध (पीपीए) है उसे सूचित करते हुए स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर (एसएलडीसी) को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (3) स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर (एसएलडीसी) माह के 7वें दिन तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर न्यूनतमदर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया माह के 12वें दिन तक तैयार करेगा, जो यदि अन्यथा पुनरीक्षित न की हो, तो माह के 16वें दिन से अन्तिम दिन तक प्रभावी रहेगी। न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया को एसएलडीसी द्वारा प्रत्येक माह के 12वें दिन 15.00 बजे तक संलग्नक-1 पर प्रारूप में कम्पनी की वेबसाइट पर डाला जायेगा।
- (4) इसी प्रकार एसएलडीसी प्रत्येक माह के 22वें दिन तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर माह के 27वें दिन तक न्यूनतमदर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया तैयार करेगा, जो यदि एसएलडीसी द्वारा पुनरीक्षित न की गयी हो अगले माह के पहले दिन से 15वें दिन तक लागू रहेगी। न्यूनतमदर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया को एसएलडीसी द्वारा प्रत्येक माह के 27वें दिन 15.00 बजे तक संलग्नक-1 पर प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर डाला जायेगा।

**6—डिस्पैच के कार्यक्रम हेतु सामान्य सिद्धान्त—**

- (1) निम्नतर दरों पर आपूर्ति हेतु निम्न सामान्य सिद्धान्त होंगे—
- अ— **ग्रिड पावर बैलेंस बनाये रखना**—वितरण अनुज्ञप्तिधारी मांग का पूर्वानुमान लगायेगा और अपेक्षित शैड्यूल तैयार करने के लिये इसका उपलब्ध उत्पादन स्रोतों के साथ मिलान करेगा। यदि उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में पूर्वानुमानित मांग अधिक है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत की क्रय के लिये अग्रिम योजना बनानी चाहिए।
- ब— **विद्युत कय लागतों को न्यूनतम करना**—वितरण अनुज्ञप्तिधारी मांग का ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा जिससे विद्युत क्रय की कुल लागत न्यूनतम हो। वितरण अनुज्ञप्तिधारी न केवल विचलनीय प्रभारों पर विचार करेगा वरन् अन्य विचलनीय लागत, जैसे स्टार्टअप तथा शटडाउन लागत, जनरेटर को कम यूनिट पर चलाये जाने का हर्जाना एवं अपेक्षित कार्यक्रम तैयार करने हेतु अन्य विचलनीय लागतों पर भी विचार करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को समस्त विचलनीय लागतों तथा सिस्टम बाधाओं को गतिशील रूप से न्यूनतम लागत आवश्यकता अनुसूची बनाने के लिए आधुनिक अनुकूलन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।
- स— **भार में कमी से बचाव—**
- (i) क्रय से पूर्व न्यूनतमदर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया निर्धारित करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा एसएलडीसी दिन के पीक घण्टों में तथा ऑफपीक घण्टों में उत्पादन बढ़ाया अथवा घटाया जा सके, भार में कमी के बचाव हेतु पर्याप्त उत्पादन इकाइयों को तैयार रखने की अग्रिम योजना तैयार करेगा।
  - (ii) क्रय से पूर्व न्यूनतमदर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया निर्धारित करते समय आपूर्ति से पूर्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तथा उत्पादन संयंत्रों का कार्यक्रम निर्धारित करते समय एसएलडीसी द्वारा इकाइयों को कम क्षमता पर चलाने अथवा बन्द करने से पूर्व उत्पादन संयंत्र के आंशिक भार पर ईंधन की खपत, ईंधन लागत से सम्बद्ध लागत सहित उनके भण्डारण दर सहित उत्पादन संयंत्र की विशिष्ट गुणवत्ता को संज्ञान में लेना चाहिए।

- (अ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा एसएलडीसी सम्यक् आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पीक घण्टों में ऊर्जा की मांग की प्रतिपूर्ति हेतु ऊर्जा संचयी संयंत्रों (बैटरी भंडारण) अथवा रिजर्वार/पोंटेज आधारित जल विद्युत संयंत्रों अथवा अन्य तकनीक/स्रोत, जो उन्हें ऑफपीक से पीक मांग घंटों में परिवर्तन के समय अधिक उपयोग की क्षमता रखते हों, को भी संज्ञान में लेंगे।
- (ब) कम मांग की स्थिति के कारण यदि स्थितियां रिजर्व शट-डाउन की मांग करती हैं, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा एसएलीडीसी को उत्पादन संयंत्र को चालू रखने की गुणवत्ता, जैसे चालू करने में न्यूनतम समय, बन्द करने में कम समय, चालू करने में ईंधन लागत तथा चालू करने में ईंधन की खपत आदि को संज्ञान में लेना चाहिए।

**द- एसएलडीसी उत्पादन संयंत्रों की संख्या का निम्न हेतु आनलाइन अनुकूलन करेगा-**

- (i) पारीगत आरईएस सूचियों के उत्पादन में आकस्मात विचलन को वहन करना।
- (ii) उत्पादनकर्ता के लिए रैम्पिंग वांछनाओं तथा चालू करने/बंद करने के लिये समय को संज्ञान में लेते हुए पीक घंटों की अवधि में मांग को पूरा करने के लिये,  
परन्तु यह कि प्रणाली बाधाओं के कारण तापीय संयंत्रों का उत्पादन कम करने/बंद करने की अनुमति न दिये जाने पर एसएलडीसी अनिवार्य रूप से चलते रहने चाहिए अथवा पारीगत आरईएस उत्पादन में कमी कर सकता है।

परन्तु यह भी कि एसएलडीसी पारीगत आरईएस में कटौती के कारण उपलब्ध करायेगा।

य- **स्पिनिंग रिजर्व की पर्याप्तता**-फ्रीक्यूंसी के स्थायित्व के लिये एसएलडीसी प्रणाली की स्पिनिंग रिजर्व की पर्याप्तता सुनिश्चित करेगा। एसएलडीसी प्रणाली की चालू रिजर्व आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जैसे, प्राईमरी कन्ट्रोल रिजर्व अथवा एफसीआर (फ्रीक्यूंसी कन्टेन्मेंट रिजर्व) सेकेंडरी कन्ट्रोल रिजर्व अथवा एफआरआर (फ्रीक्यूंसी रीस्टोरेशन रिजर्व), टर्टियरी कन्ट्रोल रिजर्व अथवा रिलेसमेन्टरिजर्व (आरआर)।

र- **विनियमावली का अनुपालन**-वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्राप्त करने की अनुसूचियाँ तैयार करते समय विभिन्न विनियमावलियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न बाधाओं तथा लागतों, जैसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमावली, 2010 तथा इसके संशोधन में स्टेशन हीट रेट में कमी, आकजलरी ऊर्जा खपत तथा प्राथमिक ईंधन की कुछ संख्याओं से अधिक खपत के नियमानुसार क्षतिपूर्ति को संज्ञान में लेना चाहिए।

ल- **प्रणाली तथा पद्धति बाधाएं**-क्रय का विवरण तैयार करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किन्हीं प्रणाली तथा पद्धति बाधाओं, जैसे ईंधन की कमी, पारेषण बाधाओं (इंटरकनेक्टेड सिस्टम के एटीसी/टीटीसी) को उत्तम कार्यक्रम हेतु संज्ञान में लेना चाहिए। इस उद्देश्य के लिये एटीसी/टीटीसी को प्रत्येक पखवाड़े एसएलडीसी की वेबसाईट पर डाला जायेगा।

व- **बाजार में अवसर**-वितरण अनुज्ञप्तिधारी को न केवल उसके स्तर पर ऊर्जा क्रय अनुबंधों के माध्यम से अनुबंधित उत्पादन बल्कि कुल ऊर्जा क्रय लागत को न्यूनतम करने के लिये कमी की स्थिति में अथवा महंगी उत्पादन लागत को बाजार के अवसरों की स्थिति में कुल क्रय लागत में परिवर्तित किये जाने हेतु विद्यमान बाजार अवसरों पर विचार करना चाहिए।

- (2) एसएलडीसी प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी से न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय का विवरण प्राप्त कर केन्द्रीय न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया तैयार करेगा। उत्पादन कम्पनी के विभिन्न लाभार्थियों द्वारा वांछित कुल विद्युत के आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विनियमावलियों के अनुसार ग्रिड की फ्रीक्वेंसी बनाये रखने के लिये समस्त प्रणाली एवं लागत बाधाओं को विचारित करते हुए उत्पादन संयंत्र का न्यूनतम लागत सिद्धान्त के प्रतिबंध के साथ एसएलडीसी उत्पादन संयंत्र का कार्यक्रम (शैड्यूल) निर्धारित करेगा।

- (3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी मांग, आपूर्ति की उपलब्धता तथा बाजार मूल्यों पर आधारित अग्रिम आरक्षित शटडाउन (आरएसडी)/आरएसडी को पुनर्जीवित करने की योजना बनायेगा :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी भी उत्पादन गृह के शटडाउन/पुनरुद्धार की योजना बनाने से पूर्व पावर एक्सचेंज और बैंकिंग आदि जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सहित कुल स्रोतों की लागत विश्लेषण करेगा।

- (4) उत्पादन इकाइयों का तकनीकी न्यूनतम पर संचालन शैड्यूलिंग तथा डिस्पैच कोड द्वारा कड़ाई से दिशा निर्देशित होगा :

परन्तु यह कि इस विनियमावली के आधार पर एसएलडीसी संशोधित शैड्यूलिंग एवं डिस्पैच कोड तैयार करेगा तथा इस विनियमावली की अधिसूचना की तिथि से 15 दिन के अन्दर आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह भी कि जहां न्यूनतमदर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय (एमओडी) का पालन नहीं किया जाता है एसएलडीसी ऐसे प्रकरणों को कारणों सहित आयोग को सूचित किये जाने हेतु प्रारूप भी विकसित करेगा।

#### 7-उत्पादन संयंत्र द्वारा क्षमता घोषित करने हेतु दिशा निर्देश-

- (1) ईंधन एवं जल की उपलब्धता को संज्ञान में लेने के उपरान्त राज्य ग्रिड कोड के प्रावधानों की अनुरूपता में उत्पादन कम्पनी उत्पादन संयंत्र से बाहर भेजे जाने वाले उत्पादन का शैड्यूल मेगावाट में प्रत्येक टाइम ब्लॉक में एक दिन पूर्व उपलब्ध करायेगी।
- (2) उत्पादन कम्पनी ईंधन तथा जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना निम्न प्रारूप में एसएलडीसी तथा अनुबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को एक दिन पूर्व आधार पर उपलब्ध करायेगी।

|               | उत्पादन शैड्यूल के अनुसार मांग | उपलब्धता | कमी पर टिप्पणी यदि कोई हो |
|---------------|--------------------------------|----------|---------------------------|
| ईंधन 1 (इकाई) |                                |          |                           |
| ईंधन 2 (इकाई) |                                |          |                           |
| ईंधन .....    |                                |          |                           |
| जल            |                                |          |                           |

- (3) दिन के शेष भाग के लिये राज्य सेक्टर उत्पादन गृहों (एसएसजीएस) द्वारा (डीसी) का संशोधन तथा लाभार्थी (लाभार्थियों) द्वारा शैड्यूल उत्पादन की मांग की अनुमति भी अग्रिम सूचना के आधार पर प्रदान की जायेगी। ऐसे प्रकरणों में संशोधित शैड्यूल/घोषित क्षमता उस टाइम ब्लॉक से गणना करते हुए जिसमें संशोधन का अनुरोध एसएलडीसी से प्राप्त हुआ है, जो पहला होगा, तीसरे ब्लाक (एन+2) से प्रभावी होगी। जैसा कि निम्न विनियम (5) में प्रावधान है ऐतिहासिक रूप से प्राप्त रैम्प अप तथा रैम्प डाउन दरों की तुलना करते समय शैड्यूल उत्पादन समीक्षा की दृष्टि से रैम्पअप/रैम्प डाउन दरों को मशीन की ओईएम विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित किया जायेगा। इस प्रकार श्रेणीवार स्पष्ट किया गया है कि अन्तःराज्य उत्पादन गृहों एवं अन्तः राज्यीय इकाइयों के लिए पुनरीक्षण आईईजीसी एवं इसमें किये गये संशोधनों के अनुसार प्रभावी होगा।
- (4) निम्न किसी भी परिस्थिति में एसएलडीसी उत्पादन संयंत्र/इकाई को उत्पादन इकाई द्वारा दिन के लिये अथवा विशिष्ट टाइम ब्लॉक के लिये उत्पादन शैड्यूल का अधिकतम डीसी का प्रदर्शन करने के लिये कह सकता है।
  - (अ) उत्पादन गृह द्वारा उत्पादन संयंत्र विशेष के लिये घोषित क्षमता पीक घण्टों में ऑफपीक घण्टों से कम होने के प्रकरण में,
  - (ब) उत्पादन संयंत्र विशेष की घोषित क्षमता वर्ष की कम मांग की अवधि में वर्ष की उच्चतर मांग की अवधि के उत्पादन शैड्यूल से अधिक के प्रकरण में,
  - (स) किसी भी उत्पादन गृह के किसी उत्पादन संयंत्र विशेष के लिये दिन के कई टाइम ब्लॉक के लिये घोषित क्षमता का विचलन अनुबंधित क्षमता के 20 प्रतिशत से अधिक होने के प्रकरण में,
  - (द) अनुबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रार्थना पर आधारित।
- (5) जैसा निर्माता द्वारा टर्बाइन का ओई एम करेक्टेस्टिक प्रमाणित उपलब्ध किया गया है उसके दृष्टिगत उत्पादन कम्पनी द्वारा रैम्प अप तथा रैम्प डाउन दरें घोषित की जायेंगी:  
परन्तु यह कि उपर्युक्त उपलब्ध करायी गयी रैम्प अप तथा रैम्प डाउन दरें उत्पादन इकाई द्वारा ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर विगत में उपलब्ध दरों से तुलनात्मक होंगी। ऐसी तुलना की पुष्टि के उपरान्त रैम्प अप तथा रैम्प डाउन दरें एसएलडीसी की वेबसाइट पर डाली जायेंगी।

- (6) उनकी घोषित क्षमता (डीसी) ईंधन तथा जल की उपलब्धता, रैमिंग आदि के संदर्भ में उत्पादनकर्ता द्वारा मिथ्या घोषणाओं की घटनाओं की पहचान करने तथा उन्हें संज्ञान में लाने हेतु एसएलडीसी एक व्यापक निगरानी और सम्प्रेक्षा प्रक्रिया विकसित कर सकता है। उत्पादनकर्ता द्वारा घोषित क्षमताओं में गेमिंग की पहचान हेतु एसएलडीसी को एक निगरानी तंत्र अथवा एक डैशबोर्ड भी विकसित करना चाहिए। सूचना एसएलडीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होनी चाहिए।
- (7) एसएलडीसी ऐसी मिथ्या घोषणा की घटनाओं की रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर डालेगा। एसएलडीसी ऐसी रिपोर्ट सम्बन्धित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भी, जिनका ऐसे उत्पादन संयंत्र/इकाइयों से ऊर्जा क्रय अनुबन्ध है, मासिक आधार पर प्रत्येक माह की 5 तिथि तक भेजेगा।

#### 8-उत्पादन संयंत्र के लिए शून्य शेड्यूल हेतु दिशा निर्देश-

- (1) यदि अपेक्षित उत्पादन उपलब्धता अपेक्षित मांग से अधिक है अथवा ऊर्जा बाजार में सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता के मामले में वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी कुल ऊर्जा क्रय लागत के अनुकूलन के लिए जिस अवधि में मांग कुल अनुबन्धित स्रोतों से उपलब्धता से कम है इसके अनुबन्धित स्रोतों में से कुछ के लिए शून्य शेड्यूल देने पर विचार कर सकता है।
- (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबन्धित उत्पादक के शून्य शेड्यूलिंग करने पर उसकी ऊर्जा क्रय लागत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :  
परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निर्णय के सम्बन्ध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए छमाही रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- (3) एसएलडीसीमांग, आपूर्ति की स्थिति और पारेषण बाधाओं पर विचार कर के वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित "शून्य शेड्यूल" पर अपनी सहमति उपलब्ध करायेगा।
- (4) यदि ग्रिड की बाधाएँ न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय (एम.ओ.डी.) की प्रक्रिया में अधिकतम विचलनीय प्रभार वाले संयंत्र की शून्य शेड्यूलिंग को रोकती हैं तब अगले अधिकतम विचलनीय प्रभार वाले संयंत्र पर विचार किये जाने की आवश्यकता होगी :  
परन्तु यह कि ऐसी ग्रिड बाधाओं के विवरण को ऐसी अवधि सहित जिसमें यह बनी रह सकती हैं एसएलडीसी प्रत्येक माह के प्रथम और 15वें दिवस को अपनी वेब साइट पर प्रकाशित करेगा।
- (5) परिवर्तनीय प्रभार में कोई भी अतिरिक्त लागत निहितार्थ (परिचालन के निम्नमान दण्ड अथवा न्यूनतम ईंधन लेने की स्थिति में) जो शून्य शेड्यूलिंग के कारण होगी, सम्बन्धित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा वहन की जायेगी तथा इसका निपटारा उत्पादक के साथ ऊर्जा क्रय के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा। एसएलडीसी की शेड्यूलिंग में गलती के प्रकरण के सिवाय अतिरिक्त ऊर्जा क्रय की ट्रूयिंग-अप करते समय ऐसी अतिरिक्त लागत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भरपाई नहीं की जायेगी।  
उपर्युक्त किसी भी कथन के होते हुए भी एसएलडीसी गलत शेड्यूलिंग निर्धारण करने वाले कारणों को सूचित करेगा और उसे वहन करेगा जिस की एसएलडीसी को एआरआरमें व्यय के रूप में भरपाई नहीं की जायेगी।

#### 9-एसएलडीसी द्वारा उत्पादन संयंत्र के रिजर्व शटडाउन (आरएसडी) के निर्देश हेतु मार्ग दर्शन-

- (1) उत्पादन संयंत्रों को न्यूनतम दर से बढ़ते हुए दर में दरों पर तथा ग्रिड की बाधाओं, यदि कोई हों, के आधार पर सख्ती से रिजर्व शटडाउन के अन्तर्गत रखे जायेंगे:  
परन्तु यह कि ऐसी ग्रिड बाधाओं को ऐसी अवधि सहित जिसमें यह बनी रह सकती हैं एसएलडीसी प्रत्येक माह के प्रथम एवं 15वें दिवस को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
- (2) जैसा कि एसएलडीसी द्वारा अपने शेड्यूलिंग एवं डिस्पैच कोड में निर्दिष्ट है कि लाभार्थी द्वारा उत्पादन संयंत्र को रिजर्व शटडाउन में रखे जाने का अनुरोध एसएलडीसी को प्रारूप आरएसडी-1 में प्रस्तुत किया जायेगा। उपर्युक्त प्रस्तावित आरएसडी के सम्बन्ध में लाभार्थी द्वारा उत्पादन गृह को समय पर सूचित करना चाहिए।
- (3) जैसा कि इस विनियमावली की विनियम (7) में निर्दिष्ट है रिजर्व शटडाउन की अवधि में एसएलडीसी द्वारा उचित रैम्प डाउन दर प्रदान की जायेगी।



- (4) उत्पादनकर्ता सुनिश्चित करेगा कि आरएसडीसी में (डीसी) मशीनों का सामान्य आकजलरी उपभोग घटाने के पश्चात् एमसीआर से अधिक नहीं है।
- (5) आरएसडी के अधीन इकाई उत्पादन गृह द्वारा अनुरक्षण की कार्यवाही नहीं की जायेगी ताकि आरएसडी इकाई सदा पुनरुद्धार सिंक्रोनाइजेशन के लिए तुरन्त उपलब्ध रहे। यदि उत्पादन गृह आरएसडी अधीन किसी मशीन का अनुरक्षण चाहता है तब लाभार्थी तथा एसएलडीसी के वांछित अनुमोदन से किया जायेगा।
- (6) न्यूनतमदर से बढ़ते हुए क्रम पर क्रय की प्रक्रिया में इस के लिए प्रदत्तग्रिड द्वारा अनुमति की शर्तों के प्रतिबन्ध के साथ आरएसडी उच्चतर विचलनीय प्रभारवाली इकाई पर लागू की जायेगी।
- (7) एसएलडीसी गत माह की आरएसडी का विवरण संलग्नक-2 पर प्रारूप में प्रत्येक माह की तीसरी तिथि तक अपनी वेब साइट पर डालेगा।

#### 10—उत्पादन गृह या इकाई (इकाइयों) के आरएसडी से पुनरुद्धार की क्रियाविधि—

- (1) रिजर्व शटडाउन से उत्पादन संयंत्रों का पुनरुद्धार दृढ़ता पूर्वक न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी/लाभार्थी द्वारा उपलब्ध पीक मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा बाजार में उपलब्ध विकल्पों को संज्ञान में लेकर किया जायेगा :  
परन्तु यह कि केवल पारेषण बाधाओं के प्रकरण में अपवाद किया जा सकता है।
- (2) एकबारआरएसडी के अन्तर्गत निकाले जाने के उपरान्त 8 घण्टे के पश्चात् इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। प्रणाली की मांग की स्थिति में एसएलडीसी के निर्देशानुसार उत्पादन इकाई को 8 घण्टे से पूर्व भी वापस लिया जा सकता है। इसी प्रकार वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी समस्त लागत निहितार्थ को देखते हुए इकाई का पुनरुद्धार 8 घण्टे से पूर्व निदेशित कर सकता है:  
परन्तु यह कि मशीन को प्रारम्भ (स्टार्ट) करने का विभिन्न परिस्थितियों में समय जैसे हाट, वार्म तथा कोल्ड क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे से अधिक न ही होगा। तथापि यदि एक उत्पादन इकाई एसएलडीसी/लाभार्थी को पूर्व सूचना देने के पश्चात् वेट प्रिजर्वेशन में रखी गयी है उसे चालू करने के लिए अतिरिक्त 6 घंटे प्रदान किये जायेंगे:  
परन्तु यह भी कि यदि मशीन निर्धारित समय में पुनरुद्धार हेतु अयोग्य है तो ऐसी उत्पादन कम्पनी औचित्य सहित कारणों को एसएलडीसी को उपलब्ध करायेगी तथा एसएलडीसी तदनुसार कार्य करेगा।
- (3) समान विचलनीय लागत वाली इकाइयों में जिसका पुनरुद्धार समय कम है उसका पुनरुद्धार होना चाहिए।
- (4) आरएसडी से पुनरुद्धार हेतु लिये जाने वाले समय की गणना एसएलडीसी द्वारा सम्बन्धित उत्पादन गृह को दी गयी सूचना के समय से की जायेगी। एसएलडीसी उत्पादनकर्ता को इकाई को (पुनरुद्धार हेतु निर्दिष्ट समय से अधिक समय में) अग्रिम पुनरुद्धार किये जाने हेतु कह सकता है।
- (5) आरएसडी के अन्तर्गत इकाई (इकाइयों) के पुनरुद्धार हेतु उत्पादन गृह के एक अथवा अधिक लाभार्थी तथा उत्पादन गृह को पुनरुद्धार उपरान्त कोयला आधारित उत्पादन गृहों को 8 घण्टे तथा गैस आधारित उत्पादन गृहों के लिए 3 घण्टे न्यूनतम चलाने का तकनीकी शेड्यूल की प्रतिबद्धता के साथ पुनरुद्धार का निर्णय ले सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उत्पादन गृह रैम्पअप/रैम्पडाउन क्षमता को संज्ञान में लेते हुए आनबार/ऑफबार घोषित क्षमता को संशोधित करेगा।
- (6) रिजर्व शटडाउन से उत्पादन इकाई के पुनरुद्धार का अनुरोध लाभार्थी द्वारा एसएलडीसी को, जैसा कि एसएलडीसी द्वारा इस के शिड्यूलिंग एवं डिस्पैच कोड में प्राविधानित है प्रारूप आरएसडी-2 में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (7) स्टार्ट-अप की अवधि, जैसा कि इस विनियमावली के विनियम 7 में विनिर्दिष्ट है, एसएलडीसी द्वारा उचित रैंप दर प्रदान की जायेगी।

मशीन की उत्पादन गृह द्वारा घोषित पुनरुद्धार अवधि अथवा एसएलडीसी द्वारा विभिन्न प्रकार की मशीनों के लिए दी हुई अवधि में मशीन का पुनरुद्धार न होने के प्रकरण में मशीन के सम्बन्धित पुनरुद्धार की अवधि से वास्तविक पुनरुद्धार तक की अवधि में मशीन को परिचालन से बाहर माना जायेगा, तथा इस अवधि में घोषित क्षमता शून्य मानी जायेगी। एसएलडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी सूचना स्टार्ट अप समय को ध्यान में रखते हुए अग्रिम रूप से उत्पादन गृह को प्रेषित की जाये।

#### 11—अन्तः राज्य पारेषण प्रणाली (आइएनएसटीएस) से सम्बद्ध अन्तःराज्य उत्पादन प्रणाली (आइएमजीएम) के परिचालन हेतु तकनीकी न्यूनतम शैड्यूल—

- (1) कोयला फायर्ड/गैस फायर्ड/विविध ईंधन आधारित एसटीयू से सम्बद्ध उत्पादन इकाइयों के सम्बन्ध में परिचालन के लिए तकनीकी न्यूनतम इस की स्थापित क्षमता का 55 प्रतिशत अथवा जैसा कि आईईजीसी के अन्तर्गत संशोधित होगा।
- (2) अन्तः राज्य उत्पादन प्रणाली (आइएनएसजीएस) एसएलडीसी द्वारा इस की इकाई (इकाइयों) को ग्रिड सुरक्षा अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बहुत कम शैड्यूल दिये जाने के कारण तकनीकी न्यूनतम अथवा अधिक पर परन्तु नार्मेटिव संयंत्र उपलब्धता गुणक से कम पर परिचालन हेतु निर्देशित किया जा सकता है।
- (3) जिस अन्तः राज्य उत्पादन प्रणाली (आइएनएसजीएस) एसएलडीसी द्वारा नार्मल प्लान्ट अवेलिबिलिटी फैक्टर से कम परन्तु तकनीकी न्यूनतम पर अथवा उससे अधिक पर परिचालन हेतु निर्देशित किया जायेगा उसे आयोग द्वारा समय-समय पर अपनी विनियमावली अथवा आदेशों में निर्दिष्टतंत्र के अनुसार क्षतिपूर्ति दिया जायेगा :  
परन्तुक यह कि उत्पादनकर्ता को देय क्षतिपूर्ति के लिए 15 दिवसों के भीतर प्रारूप विकसित करेगा तथा फलस्वरूप ऐसी क्षतिपूर्ति को प्रतिमाह उनकी वेबसाइट पर डाला जायेगा।
- (4) वाणिज्यिक डिवियेशन शटलमेंट मैकेनिज्म (डीएसएम) के अनुसार की जायेगी।

#### 12—संशोधन करने का अधिकार—

आयोग, किसी भी समय, इस विनियमावली के किसी भी प्रावधान में विचलन, बदलाव, परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकता है।

#### 13—कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार—

यदि इस विनियमावली को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा अधिनियम से, असंगत न हों, ऐसे प्रावधान बना सकता है जो कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होते हों।

#### 14—शिथिल करने के अधिकार—

अपने स्वयं के द्वारा अथवा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष आवेदन करने पर आयोग इस विनियमावली के किसी भी प्रावधान को शिथिल किये जाने से प्रभावित किये जाने वाले पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा लिखित कारणों के साथ शिथिल कर सकता है।

#### 15—प्रक्रिया निर्देश, कोड, दिशा-निर्देश निर्गत करने का अधिकार—

अधिनियम के प्रतिबन्धाधीन इस विनियमावली को लागू करने के लिए आयोग समय-समय पर प्रक्रिया निर्देश, अथवा कोड अथवा दिशा-निर्देश निर्गत कर सकता है।

#### 16—निरसन एवं संरक्षण—

- (1) जैसा कि इस विनियमावली में अन्यथा प्रावधानित है उसे संरक्षित करते हुए न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय से सम्बन्धित कोई विनियम अथवा आदेश इस विनियमावली की अधिसूचना की तिथि से समाप्त माने जायेंगे।
- (2) ऐसे निरस्तीकरण के होते हुए भी निरस्त विनियमों अथवा आदेशों के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही जब तक इस विनियमावली के प्राविधानों से असंगत नहीं है इस विनियमावली के अन्तर्गत किया हुआ अथवा अनुरूप प्राविधानों के अन्तर्गत किया हुआ माना जायेगा।

**संलग्न-1**

राज्य विचलनीय प्रभारों (वीसी) के न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय (एमओडी) की प्रक्रिया..... से..... तक के पखवाड़े के लिये

| क्रम सं० | उत्पादन गृह | विचलनीय प्रभार<br>(रु० / केडब्ल्यूएच) |
|----------|-------------|---------------------------------------|
|          |             |                                       |
|          |             |                                       |
|          |             |                                       |
|          |             |                                       |
|          |             |                                       |
|          |             |                                       |
|          |             |                                       |

**टिप्पणी**—एकल मांग टैरिफ अंतः राज्य उत्पादन गृहों के समबन्ध में न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय (एमओडी) के उद्देश्य से कुल टैरिफ विचलनीय प्रभार माना जायेगा।

**अनुलग्नक-2**

बैंकिंग डाउन आख्या दिनांक..... के लिये

| क्रम सं० | उत्पादन गृह / इकाई | बैंकिंगडाउन की अवधि<br>(टाइम ब्लॉक) |    | निर्धारित कुल डिस्पैच<br>शैड्यूल<br>(मेगावाट) |                 | बैंकिंग डाउन की मात्रा<br>(मेगावाट) | टिप्पणी |
|----------|--------------------|-------------------------------------|----|---|-----------------|-------------------------------------|---------|
|          |                    | से                                  | तक | घोषित क्षमता                                  | डिस्पैच शैड्यूल |                                     |         |
|          |                    |                                     |    |   |                 |                                     |         |
|          |                    |                                     |    |   |                 |                                     |         |
|          |                    |                                     |    |   |                 |                                     |         |
|          |                    |                                     |    |   |                 |                                     |         |

टिप्पणियाँ—

आयोग के आदेश से,  
संजय कुमार सिंह,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।

**UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****Notification No. U.P.E.R.C./ Secretary/Regulation/516***Lucknow dated : February 03, 2021***NOTIFICATION****Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Merit Order Despatch and Optimization of Power Purchase) Regulations, 2021**

In exercise of powers conferred under clause (zi) & (zp) of sub section (2) of Section 181, Section 66, clause (b), (h) & (k) of sub section (1) of Section 86, Section 61 of the Electricity Act, 2003 and all other provisions enabling in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations:

**1. Short Title and Commencement-**

- (1) These Regulations shall be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Merit Order Despatch and Optimization of Power Purchase) Regulations, 2021;
- (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

**2. Definitions-**

- (1) "Act" means the Electricity Act, 2003 and subsequent amendments thereof;
- (2) "AC-UBC" shall have the same meaning as specified under Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020;
- (3) "Agency" shall have the same meaning as defined under U. P. Electricity Grid Code 2007 and subsequent amendments thereof;
- (4) "Availability" shall have the same meaning as defined under U. P. Electricity Grid Code 2007 and subsequent amendments thereof;
- (5) "Beneficiary" shall have the same meaning as defined under U. P. Electricity Grid Code 2007 and subsequent amendments thereof;
- (6) "CEA/Authority" means the Central Electricity Authority (CEA) as defined in the Electricity Act, 2003;
- (7) "Central Generating Station" shall have the same meaning as defined under Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 (IEGC) as amended from time to time;
- (8) "Cold Start" shall have the same meaning as provided under Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time and orders thereof;
- (9) "Commission" means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (10) "Demand" means the demand of Active Power in MW;
- (11) "Declared Capacity or DC" shall have the same meaning as provided under Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time and orders thereof;
- (12) "Distribution Licensee" shall means the same as defined under Section 2 (17) of the Electricity Act, 2003;
- (13) "Ex-Power Plant" shall have the same meaning as defined under U. P. Electricity Grid Code 2007 and subsequent amendments thereof;
- (14) "Hot Start" shall have the same meaning as provided under Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time and orders thereof;

- (15) "Intra State Transmission System" shall have the same meaning as defined under Electricity Act, 2003;
- (16) "Licensee" shall have the same meaning as defined under Electricity Act, 2003;
- (17) "Market" means a platform where buyers and sellers, either directly or through Trading Licensees, or through Power Exchanges, buy or sell electricity or Renewable Energy Certificates or Energy Savings Certificates;
- (18) "Maximum Continuous Rating (MCR)" shall have the same meaning as defined under Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time;
- (19) "Merit Order Despatch (MOD)" means despatch of generating stations to supply electricity in accordance with the merit order based on variable charges taking into account any technical, regulatory and operational limits of generation and transmission facilities;
- (20) "MOD Stack" means the stack prepared on the basis of available variable charges for (n-1)th or (n-2)th month as applicable for despatch of generation in accordance with UPERC (Merit Order Despatch and Optimization of Power Purchase) Regulations, 2021 along with average inter – state transmission losses and AC-UBC charges for (n-1)th month and if not available for (n-1)th month then last available;
- (21) "Must Run Power Plants", means those wind, solar, run of the river hydro (excluding storage), nuclear power plants or municipal solid waste based power plants or any other power plants as specified by the Commission from time to time whose tariff is either determined or adopted by the Commission:  

Provided that the banking of power by the Distribution Licensees shall also be treated as must run and shall be out of the merit order despatch.
- (22) "Operation" shall have the same meaning as defined under U. P. Electricity Grid Code 2007 and subsequent amendments thereof;
- (23) "Off Bar Declared Capability in MW" shall have the same meaning as provided under Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time and orders thereof;
- (24) "On Bar Declared Capacity" shall have the same meaning as provided under Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time and orders thereof;
- (25) "Spinning Reserve" shall have the same meaning as defined under Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time and/or Orders issued thereof;
- (26) "State Load Despatch Centre (SLDC)" shall have the same meaning as defined in the Electricity Act 2003 and shall include its successor;
- (27) "Technical Minimum" shall have the same meaning as provided under Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time and orders thereof, unless otherwise specified by the Commission;
- (28) "Variable Charges" shall mean the charges other than Capacity Charges for generating plant whose tariff is determined by Appropriate Commission under section 62 of the Electricity Act, 2003, which shall be as per applicable Generation Tariff Regulations and for generating plants whose tariff is adopted by the Appropriate Commission under section 63 of the Electricity Act, 2003 shall mean the charges other than Capacity Charges as defined under the PPA;
- (29) "Warm Start" shall have the same meaning as provided under Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time and orders thereof;

- (30) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined here, but defined in the Act, or the CERC (Indian Electricity Grid Code) Regulations or Regulations of the Central Electricity Authority or any other Regulations of this Commission shall have the meaning assigned to them respectively in the Act or IEGC or Regulations of Central Electricity Authority or any other Regulations of the Commission as the case may be. In case of any inconsistency between provisions of IEGC and the State Grid Code, the provisions of IEGC shall prevail to the extent the same can be applied in the State in the views of the Commission.

### 3. EXTENT OF APPLICATION-

These Regulations shall be applicable to SLDC, all the Distribution Licensees, Generating Companies including captive generating power plants supplying power to the Distribution Licensees of the State of Uttar Pradesh:

Provided that the Must Run Power Plants shall be covered under these Regulations only after they have fulfilled their RPO or HPO targets as specified by the Commission from time to time.

### 4. GENERAL CONDITIONS AND PRINCIPLES FOR PREPARATION OF MOD STACK-

- (1) The Distribution Licensee shall verify the details of variable cost provided by the generating company in accordance with the provisions of applicable Regulations or Generation Tariff Orders or other relevant Orders issued by the Appropriate Commission from time to time.
- (2) The Distribution Licensee shall draw up the Merit Order Stack at the State periphery for Intra-State and Inter-State Generation sources after taking into account the variable cost of each generating stations as submitted by the generating company along with the inter-state transmission losses and AC-UBC charges as specified under Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020, wherever applicable:

Provided that the inter-state transmission loss and inter-state transmission AC-UBC charges for the applicable period corresponding to each generating station shall be considered based on average of (n-1)th month and in case the last month's inter-state transmission loss or charges are not available then the last available loss or charges shall be considered.

- (3) The Distribution Licensee shall submit the Merit Order Stack to the SLDC in a manner as specified in these Regulations.
- (4) The SLDC shall be responsible for coordinating the scheduling of Buyers and Sellers within its control area. The SLDC shall also be responsible for implementation of Merit Order (MOD) Stack for scheduling process considering the principles specified in these regulations, U. P. Electricity Grid Code, 2007 as amended from time to time or any other Regulations as specified by the Commission.
- (5) The SLDC may revise the MOD Stack considering the following:
  - a. Commencement of supply of power by a Generating Unit under a new arrangement/agreement as intimated by the Distribution Licensee.
  - b. Revision of Variable Charges for preparing the MOD Stack due to Generation Tariff Orders issued by this Commission as well as Central Electricity Regulatory Commission.
  - c. Impact of Change in Law in the PPAs as notified by the Distribution Licensee after approval of the Commission.

Provided that the revision in the variable charges under (b) and (c) above shall be applicable from 1st day of a month, which falls after thirty (30) days time from the date of the Order of the Appropriate Commission.

- (6) The Variable Charge for those generating plants having PPAs entered into under Section 63 of the Electricity Act, 2003 for MOD purpose shall also include impact of Change in Law. However, the Generating Company shall submit to the Distribution Licensee the impact of Change in Law event such as changes in taxes, levies, cess etc, affecting the variable charges immediately after the same is approved by the Appropriate Commission for a particular Generating Company.
- (7) For Intra-State Generating Stations (InSGS) having single part tariff, total tariff shall be considered as Variable Charge for MOD purposes.
- (8) The Variable Charges for MOD purposes shall be provided up to 3 decimal places in Rs./unit.

#### 5. PERIODICITY AND DATE OF PREPARATION OF MOD STACK-

- (1) The Generating Company shall furnish variable charges of the immediate preceding (n-1)th month by first day and 15th day of every month to Distribution Licensees for the purposes of MOD.
- (2) The Distribution Licensee shall verify and submit the details of variable charges of all the Generating Stations/ units from which they are procuring power for preparing the MOD stack based on Variable Charge of (n-1)th month. In case the Variable Charge of immediately preceding month is not available, the Variable Charge for (n-2)th month needs to be considered and submitted to SLDC for preparation of the MOD Stack by the 7th day and 22nd day of every month with intimation to the seller with whom it has the PPA.
- (3) SLDC shall prepare the MOD Stack by the 12th day of every month for the data it has received by 7th day of the month, which would be effective from the 16th day of the month till the last day of the month unless revised by SLDC. SLDC shall upload the fortnightly MOD Stack on its website in the format given at Annexure-1 by 15:00 hours on 12th of every month.
- (4) Similarly, SLDC shall prepare the MOD Stack by the 27th day of every month for the data it has received by 22nd day of every month, which would be effective from the 1st day of every subsequent month till the 15th day of that month unless revised by SLDC. SLDC shall upload the fortnightly MOD Stack on its website in the format given at Annexure-1 by 15:00 hours on the 27th day of every month.

#### 6. GENERAL PRINCIPLES FOR DISPATCH SCHEDULING-

- (1) The general principles for the least cost dispatch shall be as per the following:
  - a. Maintaining Power Balance of the Grid- The Distribution Licensee shall forecast the demand and map it with the available sources of generation to prepare the requisition schedules. The Distribution Licensee should plan in advance for procurement of power in case the forecasted demand is more than the available supply.
  - b. Minimization of power procurement costs- The Distribution Licensee shall provide the requisition schedules such that the overall costs of power procurement is minimized. The Distribution Licensee shall consider not only the Variable Charges but also other variables costs such as Start-up and Shut-down costs, compensation charges due to lower unit loadings of generators, and any other variable costs for preparing the requisition schedules. The Distribution Licensee should use advance optimization tools to dynamically consider all variables costs and system constraints to dynamically generate the least cost requisition schedules.
  - c. Avoidance of Load Curtailment –
    - (i) The Distribution Licensee, while creating MOD stack at pre-dispatch stage and SLDC while scheduling shall plan in advance for keeping sufficient number of generation units online such that the system is able to ramp-up or ramp-down during peak and off-peak hours in a day to avoid any load curtailment.

- (ii) The Distribution Licensee, while creating MOD stack at pre-dispatch stage and SLDC while scheduling should consider the Generating plant's applicable dynamic properties such as ramp rates along with the part-load fuel consumption and associated fuel costs before selecting the unit to back-down or shut-down.
- (a) The Distribution Licensee and SLDC shall also consider the ramping capabilities and storage capacities of energy storage plants or reservoir/pondage based hydro plants or any other technology/source recognized by the Appropriate Commission having capacity to provide smooth power transition to peak demand hours.
- (b) If the system conditions demand the reserve shut down of any plant owing to lower demand scenarios, the Distribution Licensee or SLDC should consider the start-up properties of the generating plant such as minimum time online, minimum time offline, start-up fuel costs, start-up fuel consumption rates etc.
- d. SLDC shall optimize the number of generating units online in order to-
  - (i) accommodate sudden variation in the generation of Intermittent RES schedules.
  - (ii) to meet the demand during the peak demand period considering the ramping requirements and the start-up/shut-down time for generators:  
 Provided that the SLDC may curtail some of the must-run or the Intermittent RES generation in case the system constraint does not allow backing/ shut-down of the thermal plants:  
 Provided further that SLDC shall provide reasons for curtailment of intermittent RES.
- e. Adequacy of Spinning Reserves- SLDC shall ensure the adequacy of the spinning reserve requirements of the system for frequency stabilization. The SLDC shall maintain the active reserve requirements of the system, namely, Primary Control Reserve or FCR (Frequency Containment Reserve), Secondary Control Reserve or FRR (Frequency Restoration Reserve), Tertiary Control Reserve or Replacement Reserve (RR).
- f. Compliance to Regulations- The Distribution Licensee, while preparing the requisition schedules, should consider various constraints and costs as stipulated by different Regulations such as the CERC (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 and its amendments such as deteriorated Station heat rate, auxiliary energy consumption and compensations in terms of primary fuel consumption levied beyond certain numbers.
- g. System and Policy Constraints- The Distribution Licensee, while preparing the drawal schedules, should also consider any system or policy constraints such as fuel constraints; transmission constraints (ATC/TTC of the interconnected system) for optimal scheduling. For this purpose the ATC/TTC shall be uploaded on the SLDC website every fortnight.
- h. Opportunities in the market- the Distribution Licensee should not only consider the contracted generation through PPAs at its disposal but also the existing market opportunities for purchasing power during deficit scenarios or replacing costlier generation after taking into account the market scenario in order to optimize overall power procurement cost.
- (2) SLDC shall prepare the centralized MOD stack by obtaining the MOD stacks from each Distribution Licensees. Based on the total power requisitioned by various beneficiaries of the generating company, SLDC shall schedule generating plant subject to the least cost dispatch principles, while considering all system and cost constraints to maintain the grid frequency within the prescribed limits as per the CERC IEGC Regulations.
- (3) The Distribution Licensee shall plan in advance reserve shutdown (RSD)/ revival from RSD based on forecast of demand, supply availabilities & market prices:  
 Provided that the Distribution Licensee shall undertake cost benefit analysis before planning shutdown/ revival of any generating station based on total power portfolio including other instruments like power exchange and banking etc.



- (4) The operation of Generating Units at Technical Minimum shall be strictly guided by the Scheduling and Despatch Code:

Provided that SLDC on the basis of these Regulations shall prepare and submit the revised Scheduling and Despatch Code, within 15 days from the date of notification of these Regulations for the approval of the Commission:

Provided further that SLDC shall also develop the formats for reporting to the Commission the instances where MOD is not adhered along with reasons thereof.

## 7. GUIDELINES FOR CAPACITY DECLARATION BY GENERATING UNITS-

- (1) The Generating Company shall provide the ex-power plant Generation Schedule in MW for each time-block on day ahead basis, in accordance with the provisions of State Grid Code, after taking into account the availability of fuel and water.
- (2) The Generating Company shall also provide the additional information regarding the fuel and water availability in the following format to SLDC and contracted Distribution Licensee on day ahead basis

|                | Requirement as per<br>Generation<br>Schedule | Availability | Remarks on<br>shortfall, if any |
|----------------|--|--------------|---------------------------------|
| Fuel 1 (units) |  |              |                                 |
| Fuel 2 (units) |  |              |                                 |
| Fuel.....      |  |              |                                 |
| Water          |  |              |                                 |
| .....          |  |              |                                 |

- (3) Revision of (DC) by State Sector Generating Stations SSGS and requisition Scheduled Generation (SG) by beneficiary (ies) for remaining part of the day shall also be permitted with advance notice. Revised schedule/declared capacity in such cases shall become effective from 3rd time block (N+2), counting the time block in which request for revision has been received in the SLDC to be the first one. Schedule generation shall be revised with a ramp up/ ramp down rate keeping in view the OEM characteristic of the machine, while comparing it with actual ramp up & ramp down rate achieved historically as provided in sub-Regulation (5) below. It is being categorically clarified that for Inter-State Generating Stations and other Interstate entities the revision shall become effective as per IEGC and its amendments thereof.
- (4) SLDC may ask the Generating Station/Units to demonstrate the maximum DC of Generating Unit for the day or Generation Schedule for the particular time block, is any of the following circumstances:
  - a. In case the Declared Capacity by any Generating Station for a particular Generating Unit during Peak Hours is lower than Off Peak hours.
  - b. In case the Declared Capacity for a particular Generating Unit during the low demand period during the year is higher than the Generation Schedule during the high demand period during the year.
  - c. In case the variation in minimum and maximum Declared Capacity by any Generating Station for a particular Generating Unit during various time blocks of the day is more than 20% of the contracted capacity.
  - d. Based on request of contracted Distribution Licensee.

- (5) The ramp up and ramp down rates shall be declared by the generating companies looking at the OEM characteristic of the turbine as certified/ furnished by the manufacturer:  
Provided that the ramp up and ramp down rates as provided above should be comparable to the rates achieved in the past by the generating units based upon historical data. After substantiating with such a comparison, the ramp up and ramp down rates shall be uploaded on the website by SLDC.
- (6) SLDC may develop a comprehensive monitoring and audit procedure to identify and report the events of mis-declaration by the generators in terms of their DCs, fuel and water availabilities, ramping capabilities etc. SLDC should also develop a monitoring mechanism or dashboard to identify 'gaming' by the generators in providing DCs. The information should also be available on SLDC website.
- (7) SLDC shall prepare the report of such instances of mis-declaration and publish the report on its website. SLDC shall also send such report to the concerned Distribution Licensee having PPA with such Generating Plant/Units on monthly basis by 5th of every month.

#### **8. GUIDELINES FOR 'ZERO SCHEDULE' FOR GENERATION UNITS-**

- (1) If the anticipated generation availability is more than the anticipated demand, or in case there is cheaper power available in the power markets, the Distribution Licensee may consider giving Zero Schedule to some of its contracted sources for the period during which the demand is expected to be lower than the total contracted sources availability put together for optimising its power procurement cost.
- (2) The Distribution Licensee shall ensure that, there shall not be any adverse impact on its power procurement cost on account of zero scheduling of contracted generator:  
Provided that, the Distribution Licensee shall submit six monthly reports regarding such decisions to the Commission for each financial year.
- (3) SLDC shall provide its concurrence to the proposed "Zero Schedule" by Distribution Licensee considering the demand-supply position and transmission constraints.
- (4) If grid constraints prevent the Zero Scheduling of the Unit with the highest Variable Charge in the MOD Stack, the Unit with next highest Variable Charge needs to be considered:

Provided that SLDC shall publish the details of such grid constraints, along with the period for which it is likely to persist on its website on 1st and 15th day of every month.

- (5) Any additional cost implication in Variable Charges (by means of inferior norms of operation or minimum fuel off-take conditions) that arises on account of Zero Scheduling shall be borne entirely by such Distribution Licensee and shall be dealt as per provisions under PPA with generators. Pass through to the Distribution Licensee on this account will not be allowed, while truing up the power procurement cost unless it is a case of scheduling error on account of SLDC.

Notwithstanding anything provided above, SLDC will have to notify the reasons for such incorrect scheduling and shall be borne by SLDC which shall not be allowed as a pass-through expenditure in its ARR.

#### **9. GUIDELINES FOR INSTRUCTING RESERVE SHUT DOWN (RSD) OF GENERATING UNITS BY SLDC-**

- (1) Generating units are to be put under reserve shutdown is strictly on the basis of merit order dispatch and grid constraints if any:  
Provided that SLDC shall publish the details of such grid constraints, along with the period for which it is likely to persist on its website on 1st and 15th day of every month.
- (2) Request for putting generating units under reserve shutdown to be submitted by the beneficiary to SLDC in format RSD – I as specified by SLDC in its Scheduling and Despatch Code. Beneficiary should also intimate to generating station timely regarding above proposed RSD.

- (3) Appropriate ramp-down rate shall be allowed by SLDC during reserve shutdown as specified under Regulation (7) of these Regulations.
- (4) The generator shall ensure that the DC is not more than the MCR less normative auxiliary consumption of the machines under RSD.
- (5) No maintenance activities on unit under RSD shall be undertaken by the generating station so that the RSD unit is always readily available for revival/synchronization. If a generating station requires maintenance on any machine under RSD, then the same shall be done in due approval with beneficiary and SLDC.
- (6) The RSD should be applied to Units with higher Variable Charges in the MOD Stack, subject to grid conditions permitting the same.
- (7) SLDC shall upload details of the RSD of the previous month in the format at Annexure 2 on its website by the 3rd of every month.

#### **10. METHODOLOGY FOR REVIVAL OF GENERATING STATION OR UNIT(S) FROM RESERVE SHUT DOWN (RSD)-**

- (1) The Generating units shall be revived from reserve shutdown strictly on the basis of merit order and after taking into account other cheaper options available in power market to meet the peak demand by the distribution licensee/ beneficiary:

Provided that exceptions can be made only in case of transmission constraints.

- (2) Once a unit is taken out under RSD, it can be recalled any time after 8 hours. In case of system requirements, the generating unit can be revived before 8 hours as per the instructions of the SLDC. Similarly, distribution licensee can also direct revival of a unit before 8 hours looking at overall cost implication:

Provided that the time to start a machine under different conditions such as HOT, WARM and COLD shall not be more than 4 hours, 8 hours and 12 hours respectively. However, if a generating unit under RSD is put under wet preservation after prior intimation to SLDC/ beneficiary, additional six hours will be allowed to start the unit:

Provided further if machine is unable to revive within the prescribed time, such generating company shall provide the reasons along with justification to the SLDC and SLDC shall act accordingly.

- (3) In units with same variable cost, whose revival time is less, should be revived first.
- (4) Time taken to revive the unit from RSD shall be counted from the time of intimation given by SLDC to concerned generating station. SLDC may intimate generator to revive the unit in advance (more than specified time to revive the unit).
- (5) One or more beneficiaries of the generating station as well as the generating station may decide for revival of unit(s) under RSD with commitment for technical minimum schedule with minimum run time of 8 hrs. for Coal based generating stations and 3 hrs. for Gas based generating stations post revival. In such situations, the generating station shall revise the On Bar and Off Bar Declared capacity with due consideration to ramp up/ ramp down capability.
- (6) Request for revival of generating unit from reserve shutdown is to be submitted by the beneficiary to SLDC in format RSD 2 as provided by SLDC in its Scheduling and Despatch Code.
- (7) During start-up, appropriate ramp-up rate shall be allowed by SLDC as specified under Regulation 7 of these Regulations.

- (8) In case the machine is not revived as per the revival time declared by the generating station or the time given by the SLDC for different types of machine to start, the machine shall be treated under outage for the duration starting from the likely revival time and the actual revival time upto DC during such duration shall be considered as zero. SLDC shall ensure that intimation is sent to the generating station in advance keeping in view its start up time.

#### **11. TECHNICAL MINIMUM SCHEDULE FOR OPERATION OF INTRA-STATE GENERATING SYSTEM (InSGS) (GENERATING UNITS) CONNECTED TO INTRA-STATE TRANSMISSION SYSTEM (InSTS) -**

- (1) The technical minimum for operation in respect of a coal fired/gas fired/multi fuel based thermal generating unit connected to the STU shall be 55% of its installed capacity or as amended under IEGC.
- (2) InSGS may be directed by SLDC to operate its unit(s) at or above the technical minimum but below the normative plant availability factor on account of grid security or due to the fewer schedules given by the Distribution Licensee.
- (3) InSGS, which will be directed by SLDC to operate below normative plant availability factor but at or above technical minimum, shall be compensated as per the mechanism specified by the Commission through its Regulations or orders from time to time:  
Provided that SLDC within 15 days shall develop required formats for compensation payable to generators and the resulting compensation shall be uploaded on their website each month for such station.
- (4) The commercial arrangements shall be made as per applicable Deviation Settlement Mechanism (DSM).

#### **12. Power to Amend-**

The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

#### **13. Power to Remove Difficulties-**

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

#### **14. Power to Relax-**

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected by grant of relaxation, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

#### **15. Power to issue Practice Directions, Code, Guidelines-**

Subject to the provisions of the Act, the Commission may, from time to time, issue Practice Directions or Code(s) or Guidelines with regard to implementation of these Regulations.

#### **16. Repeal & Savings-**

- (1) Save as otherwise provided in these Regulations, any earlier Regulation or Order dealing with merit order despatch stands repealed from the date of notification of these Regulations.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the repealed Regulations or orders shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these Regulations, be deemed to have been done or taken under corresponding provisions of these Regulations.

